Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 20 अंक 08 30 अगस्त, 2020 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

पुलिस सुधार आवश्यकता, चुनौतियां एवं समाधान

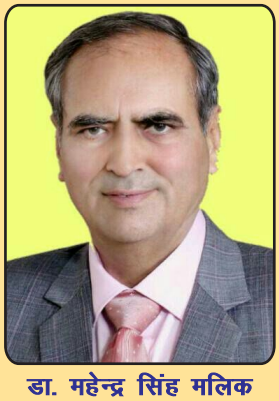

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

पिछले महीनों में पुलिस के प्रति लोगों की हमदर्दी पहले कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान और इसके बाद हरियाणा और पडोसी राज्य उत्तर प्रदेश की दो घटनाओं के बाद बढी है। ये एक अच्छा संयोग है कि पुलिस के प्रति लोगों के रवैए में असर पड रहा है। सोनीपत में गश्त पर निकले दो पुलिसकर्मियों की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या करने के बाद लोगों की सहानुभूति पुलिस के साथ खडी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात विकास दूबे और उसके गैंग के बदमाशों ने आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। हालांकि विकास दूबे इसके बाद पुलिस से बचता हुआ राज्य दर राज्य खाक छानता फिरा और अंततरू एक कथित एनकांउटर में अपने अंजाम तक पहुंच गया फिर से पुलिस सुधारों पर चर्चा शुरू हुई लेकिन उसे हकीकत में जमीन पर आज तक नहीं उतारा जा सका है।

कभी निरीह जनता पुलिसिया प्रताड़ना का रोना रोती है, तो कभी पुलिसकर्मी ही व्यवस्था के दोषों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सभ्य समाज में हर समय किसी न किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था अवश्य रही है। पुलिस हमारी उम्मीदों को पूरा क्यों नहीं कर पाती, पुलिसिंग की स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट में इसके अनेक कारण बताए गए हैं, जिनमें ड्यूटी का समय निर्धारित न होना, त्यौहारों पर छुट्टियां न मिलना, इसके अतिरिक्त कार्यकाल के दौरान मात्र 6 फीसदी को अतिरिक्त ट्रेनिंग मिल पाना शामिल है। पुलिस से लोगों का भरोसा और अपराधियों का डर दिनोंदिन कमजोर हो रहा है। पुलिसिंग का कार्य भारत में दिन–प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष ड्यूटी के दौरान लगभग 500 से 800 पुलिसकर्मियों की जानें जाती हैं। इसके साथ–साथ मानसिक तनाव व अन्य बीमारियों के कारणवश भी बहुत से पुलिसकर्मी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। यह आंकड़ा विश्व के अन्य देशों में 8 से 10 तक ही सीमित रहता है। भारत में पुलिस को न तो आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं और न ही पुलिस पर विश्वास किया जाता है।

प्रायः देखने में आया है कि पुलिस तंत्र में निचले स्तर के अधिकारियों को बाहरी चुनौतियों के बारे में ही बेसिक ट्रैनिंग दी जाती है जबकि अपराधी तंत्र से निपटने व मानवाधिकार संबंधी जैसे जरूरी मामलों से संबंधित उनको कोई जानकारी नहीं होती है इसलिए निम्न स्तर की घटनाओं की तफतीश भी अपर्याप्त जानकारी के कारण प्रभावित होती हैं और अपराधियों को ठेठ पुलिस रणनीति की प्रायः पहले ही जानकारी हो जाती है इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली में साइबर क्राईम, परिष्कृत गैजेट और अपराधियों द्वारा बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शामिल की जानी चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली में राजनैतिक दलों व दंबग नेताओं का काफी हस्तक्षेप रहता है। यही कारण है कि राजनैतिक दल पुलिस सुधारों के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखते हैं इसलिए राजनैतिक तंत्र की शह पर बढ रहे अपराधिक वर्ग पर लगाम कसने के लिए राजनीतिज्ञों, अपराधियों व पुलिस के तीन पाया टूल को प्रभावहीन करना आवश्यक है ताकि जनता पुलिस में विश्वास बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिएं लेकिन भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 189 पुलिसकर्मियों की ही स्वीकृति है और उसमें भी लगभग 35 प्रतिशत की कमी है। राज्य पुलिस में महिलाओं की नफरी काफी कम है। अभी हाल में हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस बल में महिलाओं की 15 प्रतिशत भागीदारी की गई, जिसे बढाकर 50 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में बढ़ रहे महिला विरूद्ध अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। जहां एक तरफ संख्या बल में कमी है वहीं दूसरी तरफ पुलिस बलों के लिए वाहनों की कमी और फोरेंसिक सपोर्ट नाममात्र का है। इसके साथ–साथ संरचनात्मक कमियां भी हैं। बहुत सारे मौकों पर पुलिसकर्मी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन तो करना चाहते हैं लेकिन वाहनों की कमी या स्टाफ की कमी से वे ऐसा नहीं कर पाते। इन सबके बावजूद भी पुलिस हमारी सेवा में दिन–रात लगी रहती है। भारत के अधिकतर राज्यों में पुलिस कर्मियों को लगभग 18 घंटों तक ड्यूटी करनी पड़ती है।

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

सबसे पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसे पुलिस प्रशासन की बात की, जो कंपनी के प्रति वफादारी निभाए। तभी से दरोगा के पद का सृजन हुआ। 1860 में भारतीय दंड संहिता और 1861 में दंड प्रक्रिया संहिता के अस्तित्व में आने के बाद एक पुलिस संहिता की जरूरत महसूस की गई, जिससे आपराधिक विधि का प्रवर्तन कराया जा सके। इसलिए 1860 में गठित पुलिस आयोग के आधार पर 1861 का पुलिस अधिनियम बनाया गया, पर इसकी आलोचना 1902 से ही प्रारंभ हो गई, जबकि लॉर्ड कर्जन ने एएचएल फ्रेजर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और सुधार की संभावना तलाशी। उस समय से ही पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, उसके अपराधीकरण, प्रतिक्रियावादी और क्रूर होने पर प्रश्न उठने लगे। पुलिस से हम सदा आज्ञाकारी, वफादार, सक्षम और कुशल होने की अपेक्षा करते हैं। अगर उसके कार्यों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे समाज के समस्त कार्यों का भार इस एक व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। चाहे वह अपराध नियंत्रण और निवारण का कार्य हो, कानून–व्यवस्था, जेल की व्यवस्था बनाए रखने या फिर भीड़ नियंत्रण, बीमारी, आपदा या कोई विशेष कार्यक्रम हो, किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन हो, हर जगह अगर किसी से अपेक्षा की जाती है तो वह है पुलिस।

आज आम आदमी को अपराधी से जितना डर लगता है, उतना ही डर पुलिस से भी है। उदाहरणार्थ किसी अपराधी गिरोह द्वारा हत्याएँ किये जाने अथवा किसी बड़े बैंक में डकैती डालने की घटना सामने आते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, जब अपराधी अपना काम करके निकल जाते हैं तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और पुलिस को देखते ही पुनः एक बार फिर अपने घरों के खिड़की, दरवाजे बंद कर लेते हैं। इन घटनाओं से तो यही प्रतीत होता है कि पुलिस ने जनता का सहयोगी होने के अपने दायित्व को भूला दिया है।

जैसे–जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है उसमें साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है । जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया हो तो फिर पुलिस व्यवस्था कैसे इससे अछूती रह सकती है। हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुरूप बनाना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करेंगे तथा उन्हें समाज विरोधी तत्वों से बचाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प हो, वह जैसे ही सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ करता है उसका तबादला कर दिया जाता है। दरअसल, पुलिस व्यवस्था में सुधार के जो पहलू हम फिल्मों में देखते हैं, व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं है।

पुलिस व्यवस्था में बदलाव एक संगठन में लाए जाने वाले बदलावों की तर्ज पर ही लाया जा सकता है और कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रवृत्ति में रातोंरात बदलाव नहीं ला सकता है। लेकिन तबादलों से तंग वरिष्ठ अधिकारी वर्ग अब तो जैसे सुधारों की प्रक्रिया से ही तौबा कर चुका है। पुलिस व्यवस्था में जड़ जमा चुकी इस विसंगति को बदलने के लिये पुलिस सुधार तो करना ही होगा।

पुलिस की मुठभेड़ का तरीका भी आंतरिक तौर से खतरनाक है। मुठभेड़ विशेषज्ञ अच्छे पुलिस वालों पर दांव खेलते हैं। वे सूचना देने वाले गैंग की अपराधिक गतिविधियों की माफी का बहाना ढुंढ़ते हैं जिससे उनके अपराध निश्क्रिय होते ही जबरन वसूली बढ़ जाती है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना से होने वाली मुलजिमों की मृत्यु से भी पुलिस की छवि दागदार हो रही है। राष्ट्रीय क्राईम रिकार्ड ब्युरो के अनुसार वर्ष 2010 से 2018 के बीच 853 व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई। इनमें से अकेले 2018 के दौरान 70 मौतें हुई। पुलिस थानों में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा सुप्रीमकोर्ट द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अवहेलना करना एक रूटीन का कार्य बन गया है जिससे गैर कानूनी तरीकों द्वारा तफतीश से पुलिस हिरासत के केस बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस व जनता के बीच परस्पर समन्वय व तालमेल बनाने के लिए पुलिस मित्र (एफ ओ पी) प्रणाली शुरू की गई है। पुलिस सुधार की यह प्रणाली भी कारगर साबित नहीं हुई। हाल ही में तामिलनाडू में पुलिस हिरासत में हुई छोटे दुकानदार व उसके लड़के की मौत से पुलिस के नकारात्मक रवैये से यह साबित हो गया कि छोटे कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में इस सिस्टम का सरेआम दुरूपयोग किया जाता है। पुलिस के इस प्रकार के गैर कानूनी व गैर जिम्मेवार तरीके कानून के शासन तथा कानून की भूमिका में बढ़ रहे फासले को उजागर करते हैं। पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए पुलिस थाना स्तर पर न्यायिक सुधारों की पालना व अनुशरण किया जाना जरूरी है।

वर्ष 1984 में भारतीय कानून आयोग ने पुलिस हिरासत में जख्मी होने पर व्याख्या करके स्पष्ट किया है कि पुलिस हिरासत में अगर किसी व्यक्ति का शरीर जख्मी या मौत होती है तो कानून के अनुसार स्पष्ट तौर से पुलिस हिरासत के समय तैनात पुलिस अधिकारी इसका उत्तरदायी

ईश्वर चाहते हैं कि आदमी मेहनत करके जीविका कमाये। बिना मेहनत किये खाना चोरी के समान है। –महात्मा गांधी

होगा लेकिन 36 साल बाद भी इस व्यवस्था की पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत से अपराधी जिनका पुलिस लाक अप की प्रताड़ना से ही अंत हो जाता है जो समाज के गरीब तबके से ही होते हैं और जिनकी ज्यादा अपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं होती व चोरी जैसे छोटे अपराधों के कारण ही जघन्य अपराधी करार दिए जाते हैं और मजबूरीवश अपराध की दलदल में फंसे ऐसे आरोपियों की जिंदगी क्रुर कानून उल्लंघन कर्त्ताओं द्वारा तबाह कर दी जाती है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना तो वर्ष 1977 में कर दी गई थी, लेकिन पुलिस सुधारों की चर्चा को जीवंत रखने और शीर्ष न्यायपालिका में ले जाने का श्रेय प्रकाश सिंह को जाता है। वर्ष 1996 में पूर्व पुलिस महा निदेशक, प्रकाश सिंह ने 1977–81 के पुलिस आयोग की भुला दी गई सुधार–सिफारिशों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसके फलस्वरूप दस वर्ष में सुनाए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, पुलिस को राजनीति और नौकरशाही के बेवजह दबावों से मुक्त करने और उसकी कामकाजी स्वायत्तता को बाह्य निगरानी के अपेक्षाकृत व्यापक माध्यमों से संतुलित करने पर बल दिया। हालाँकि, इन निर्देशों का (कुछ हद तक केरल को छोड़ कर) तमाम राज्यों और केंद्र ने भी अब तक छद्म अनुपालन ही किया है। जिन राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल हो रहा है वहाँ भी वरिष्ठ अधिकारियों को दो साल की बात कौन करे यहाँ तक कि दो महीने में ही तबादला कर दिया जा रहा है और कहीं से विरोध की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यह दिखावटी सुधारों की ही स्थिति है। वस्तुतः पुलिस सुधार की वर्तमान कवायद पुलिस को सत्ता के प्रतिष्ठान से मुक्त करने की कोशिश पर आधारित है। इस कयावाद में पुलिस को बाह्यः निगरानी के माध्यम से संतुलित रखने की परिकल्पना भी शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस सुधार के लिये ये सारे प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन इन प्रयासों के साथ–साथ पुलिस को नागरिक–संवेदी बनाने पर भी बल देना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का पुलिस सुधार मुख्यतः स्वायत्तता, जवाबदेही और लोकोन्मुखता के बिंदुओं पर केंद्रित है। पुलिस की स्वायत्तता को मजबूत कर उसे बाह्यः दबावों से मुक्त रखने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि डीजीपी, आइजी, एसपी, एसएचओ की दो वर्ष की निश्चित तैनाती मिलनी चाहिए तथा डीजीपी और अन्य चार वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक स्तर तक के तबादलों का अधिकार दिया जाना चाहिये। पुलिस को कानूनी दायरे में रखने के लिये राज्य पुलिस आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की अवधारणा पर भी विचार किया गया। राज्यों को नए सिरे से लोकोन्मुख पुलिस अधिनियम बनाने का निर्देश दिया गया।

पुलिस सुधारों की प्रकृति के संबंध में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक की सारी कयावाद कागज पर शानदार, पर व्यवहार में 'नई बोतल में पुरानी शराब' से ज्यादा कुछ नहीं है! क्योंकि उपरोक्त प्राधिकरणों के गठन और कार्य–संस्कृति में सरकारों की न केवल निर्णायक भूमिका होगी बल्कि उनके पास पुलिस को घुटने पर लाने के लिये भी हजारों तरीके उपलब्ध रहेंगे। इसकी पूरी सम्भावना है कि दो वर्श की स्वायत्तता के लिये कोई भी पुलिसकर्मी अपना पैंतीस वर्श का सेवाकाल और सेवा–उपरांत फायदा दाँव पर नहीं लगाएगा। अतः वर्तमान सुधारों में पुलिस बल को बिना अदालती आदेश और जाँच–पड़ताल के डर के नागरिक–संवेदी बनाए जाने को भी जोड़ना होगा। हमें समझना होगा कि लोकतांत्रिक पुलिस सुधार का क्रियाशील आधार एक सशक्त समाज ही हो सकता है, न कि समाज–निरपेक्ष पुलिस स्वायत्तता। पुलिस के वर्तमान कामकाजी संबंधों के अंतर्गत ही एक संवेदी और लोकोन्मुख कानून–व्यवस्था का निर्माण, प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से हासिल कर पाना संभव नहीं होगा। अतः पहले पुलिस नियुक्तियों की गुणवत्ता में वृद्धि करनी होगी। चूँकि पुलिस में आया हुआ व्यक्ति हमारे बीच का ही है, इसलिये पुलिस सुधारों की रुपरेखा तय करते समय समाजशास्त्र के नियमों को भी ध्यान में रखना होगा।

सुरक्षा तंत्र के मुख्य पहलू सुरक्षा की भावना व आम नागरिकों की स्वंतत्र व्यवस्था द्वारा वास्तविक लोकतांत्रिक अपराधिक न्यायिक व्यवस्था की क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। पुलिसिंग व्यवस्था के अहम पहलु मुलजिम की गिरफतारी व जमानत प्रक्रिया में विश्वसनीय/जरूरी सुधार किया जाना आवश्यक है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जुलिया रीबैरो ने आईपीएस क्लास को पत्र लिखकर स्वच्छ व चहुमुखी पुलिसिंग व्यवस्था के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है। हाल ही में विकास दुबे एनकांउटर के संबंध में गठित जुडीशियल कमीशन की रिपोर्ट भी सही तथ्यों को पेश कर शायद ही पुलिस सुधार के लिए सुझाव पेश कर सके क्योंकि वास्तविक तथ्यों से पुलिस व प्रशासन भली–भांति वाकिफ है। हाल ही में बिहार में न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने गैंग रेप पीड़िता व उसकी दो सहायकों को धारा 164 के तहत दर्ज कराए जा रहे बयान पर हस्ताखर करने को लेकर हुए वाद–विवाद के कारण जेल भेज दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक संगीन

धैर्य रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। -ससो

अपराधी द्वारा जमानत पर आने के बाद सरेआम रेप पीड़िता व उसकी मां को ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया। इस प्रकार की अपराधिक वारदातों से स्पष्ट है कि न्यायिक व पुलिस सिस्टम पर राजनैतिक भ्रष्ट तंत्र हावी है। इसलिए पुलिस बल के साथ–साथ न्यायिक प्रणाली में निष्पक्ष व स्वतंत्र सुधार लाना अति आवश्यक है। बेहतर पुलिस व्यवस्था कायम करने के लिए विधान सभाओं व संसद में गंभीर अपराधियों को प्रवेश पर रोक लगाने व पुलिस सुधार के लिए वर्ष 2006 की सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही राष्ट्र में तेजी से पनप रहे माफिया व अपराधिक तंत्र के गठजोड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस, सी बी आई, एन आई ए, इंटेलिजैंस ब्यूरो, आयकर विभाग, रैवन्यू इंटेलिजैंस व प्रवर्तन निदेशालय आदि मुख्य विभागों/ऐजेसिंयों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सक्षम पुलिस सुरक्षा तंत्र कायम किया जाना चाहिए।

निष्कर्श के तौर पर कहा जा सकता है कि "जाके पांव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई"। पुलिस सुधारों के सन्दर्भ में यह कथन एकदम सटीक बैठता है। स्वतंत्रता–प्राप्ति के साथ ही यह मान लिया गया कि प्रशासनिक मशीनरी अपने आप लोकोन्मुख हो जाएगी। लेकिन जब राजनीतिक सत्ता का चरित्र ही खास नहीं बदला तो नौकरशाही या पुलिस का कैसे बदलती। पुलिस सुधार, केवल 21वीं सदी की जरूरत नहीं है बल्कि आजादी के बाद से ही इसमें सुधार की गुंजाईश थी जो समय के साथ और बढ़ती चली गई। "एक मजबूत समाज अपनी पुलिस की इज्जत करता है और उसे सहयोग देता है, वहीं एक कमजोर समाज पुलिस को अविश्वास से देखता है और प्रायः उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है"। अतः पुलिस सुधारों को सामाजिक कल्याण से जोड़कर ही इनके वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ व पंचकुला

Congratulations

Jat candidates who got selected Civil Services Exam (Indian Administration Services-2019)

Sr. No.	Name	Rank
1.	प्रदीप मलिक	01
2.	नताशा माथुर	37
3.	दीपंकर चौधरी	42
4.	ऐश्वर्या श्योराण	93
5.	अनिशा तोमर	94
6.	शिखर चौधरी	97
7.	अपराजित	174
8.	अंचल चौहान	183
9.	रिंकू	232
10.	निकस कुमार	234
11.	अभिनव चौधरी	238
12.	आशीष जून	271
13.	मनीष चौधरी	347
14.	मनीष कुमार चौधरी	390
15.	वैभव चौधरी	451
16.	गरिमा दहिया	458
17.	महिमा खीचर	479
18.	सुमन नाला	508
19.	दीपक धनखड़	520
20.	जगदीप ढाका	543
21.	राजेंद्र चौधरी	554
22.	आकाश चौधरी	586
23.	शक्ति सिंह आर्य	587
24.	रेहान खत्री	596
25.	मुनीश कुमार	604
26.	राम जाखड़	605
27.	भानु सिंह अहलावत	618
28.	मनदीप कुमार	682
29.	श्रेया चौधरी	692
30.	पुष्पेंद्र गहलोत	706
31.	अरुण तोमर	723
32.	रेणु दहिया	
33.	प्रदीप कुमार	820
34.	पंकज कुमार चौधरी	821

जितनी भलाई माता–पिता अथवा भाई–बंधु कर सकते हैं, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। –गौतम बुद्ध

China's Surgical Strike in Ladakh

- R. N. Malik

China attacked India in September 1962.Our forces were thoroughly unprepared to face this kind of heavy attack being short of arms, ammunition , logistics and acclimatisation at such heights. Krishna Menon, the Defense Minister, was of highly overbearing nature and ignored and ridiculed the military generals. Americans called him a wasp. As a result, our forces were overrun in both Ladakh and eastern sectors. China unilaterally declared ceasefire on October 20.Jawaharlal Nehru, our Prime Minister, was shocked beyond measure because he had invested too much in China politically. But still he mustered enough courage, unlike the present Prime Minister, and called China the aggressor and called her action as an act of perfidy. He addressed the nation for full 40 minutes explaining how India helped and advocated China's cause at the international levels in the past . He wrote a long letter to all the heads of the governments explaining China's odd behavior. Our Ambassador B. K. Nehru met John Kennedy and handed over that letter personally. Kennedy's first remark was, "Is Krishna Menon still your Defense Minister? " B. K. replied in the affirmative. Then Kennedy remarked, "Only God will save your country. "

At the request of Atal Bihari Vajpayee, Nehru called the special Session of the Parliament. Nehru was pilloried for this humiliating defeat. Finally Krishna Menon, Gen. B. M. Kaul and Gen. Thappar, the C-in-C(father of journalist Karan Thappar) had to go. Gen. J. N. Chaudhary took the place of Thappar. Lt. Gen. Sam Manekshaw (hero of 1971war) took over the Eastern command. Jawaharlal Nehru did not recover from the shock and had a paralytic attack at Bhuneswar Congress session. His tendency to overwork ultimately hastened his death in May 1964.There was no able leader to cheer and encourage Nehru and tell, "Do not lose heart. Take courage. Arm our forces. Lt. Gen. Manekshaw is bold enough to do the rest. " China was weaker than India at that time and six months preparation was enough to defeat China.

Indian relations with China remained frosty till 1986 when Rajiv Gandhi visited China .Deng Xioping the helmsman of China treated Rajiv Gandhi with great warmth. Thereafter there was no problem at Chinese border till 2017.China's exports to India now value at 90billion dollars whereas the imports from India are worth only 9 billion dollars.

After Godhra riots, U. S. did not issue the visa to Sh. Narendra Modi for a visit to U. S. So he started visiting China to cultivate his relations in the name of bringing investment. His total visits to China till date are 14.After becoming Prime Minister, he invited Xi Xinping, the Chinese Head, to India. Breaking the old tradition, he straightaway landed at Ahemdabad. His reception at Sabarmati Ashram was a great spectacle when he was made to swing in a Jhoola. A similar spectacle was created during his second visit at the luxurious resort of Mallalapuram near Chenai in 2018. This bonhomie between two great leaders of two great countries of the world ended soon when China started taking sides of Pakistan on many issues at international fora. There was the first big stand-off between the armies of the two countries for over two months at Doklam. It was said that Chinese had to relent and stand of Indian Army took precedence. Media extolled the Prime Minister as a tough negotiator. He was deemed as the first Indian leader who could stand against a bully. But retired Maj. Gen. Asok Mehta and others maintain that China got what she wanted and was the clear winner and let off the hook. China was further emboldened to nibble Indian borderlands. Remember how a weak India gave a bloody nose to China in 1967.But at that time Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister and not a pompous Narendra Modi. Things would have been different had Gen. Manekshah been the C-in-C of Indian Army today.

Recently, China's behavior towards India has become very fretful and belicose . This sudden change in attitude is attributed to three reasons. . Firstly,India did not join hands with China in two projects I. e. Belt Road Initiative (BRI) and Comprehensive Regional Economic Partnership program. Many economists wrote that the two projects were in India's interests. Secondly Home Minister Amit Shah declared in the Parliament that the next effort of the government would be to take over POK and Aksai Chin. Thirdly, what really irritated China was India's open support to America, Japan and Australia (QU AD) over the South China Sea issue. The heart felt desire of Chinna was that India should completely align with China to form a Third Power Block after US and Russia. Chinese leaders have said many times that China --India partnership can be highly useful for both the countries. Now as a counter measure, China is forming her own QUAD with Turkey, Iran and Pakistan. She is creating a hostility ring around India by winning over Nepal and Bangladesh. But one conclusion is sure. The Prime Minister did not take any lession from the mistake of Nehru in romancing with

Chinese leaders. Like him, he too should not have invested too much political capital in Xi Xinping.

In Ladakh sector, there are grey areas or buffer zones between the Lines of Actual Control of the two countries. It was agreed that, in this zone, armies of the two countries could do only patrolling and nothing else. For example, in Galwan valley, Indians soldiers can patrol between Finger 8(Indian LAC) to Finger 4(Chinese LAC) and vice-versa. Chinese soldiers started misbehaving with Indian soldiers in April 2020 on minor pretexts. Then in May, they prevented the construction of a short cut road to Daulat Beg Oldi where we have also an aerodrome. Then on one fine day Chinese soldiers encroached the grey zone of Galwan valley and Depsang. Our army did not retaliate but opted for negotiations. Finally on 6th June, in a meeting of Core Commanders, a disengagement plan was agreed with initial withdrawal of 2kms by both sides. This was a fatal mistake on our behalf to agree to withdraw in our own territory. The media did not create much ado about this event till now.

On 16 June the whole nation was shocked beyond belief when TV channels flashed the bad news that our 20 soldiers were killed in a scuffle with Chinese soldiers. Surprisingly neither the Army H/Q nor the government made any statement throughout the day. Media did not have the guts to question the government for its silence over this ghastly tragedy. The media could not give any details of the skirmish except to tell the names of Col. Santosh Babu and few more soldiers.

Next day again, only media told from its own sources that 76 jawans were injured and 20 with serious injuries. It was also stated that about 40 Chinese soldiers were also killed. This information was based on the interception of a wireless message. Later it was stated that an American agency also confirmed this fact. Army H/Q still kept mum and withheld the truth.It is also said that a Colonel level officer never goes with the patrolling party. What exactly happened is still an enigma wrapped In mystery. In case of Surgical and Balakot strikes, an Army officer daily briefed the media enthusiastically. But no such thing now.

Only in the evening of 17th June the Prime Minister made a two line statement, "Our soldiers died while killing others and their sacrifice will not ne allowed to go waste. " On the third day, The Prime Minister called a meeting of Leaders of Opposition in the evening. It was not revealed who said what. Only a wrap up statement by the Prime Minister was reported. The Prime Minister declared that, "No body had encroached Indian territory, nobody has encroached and nobody will be allowed to encroach Indian territory. " All the friendly countries were shoked at this statement for giving a clean chit to China. They called our Ambassadors and told them clearly ,"How can we condemn China when your own Prime Minister is giving a clean chit to China ?"Only then (19th June).PMO clarified that the statement of the Prime Minister was referring the situation after 15th June only. But the damage by that time was done as China could know that Prim Minister was greatly subdued. However, BJP spokespersons brazenly continued to deny Chinese occupation of the area between Finger 4 and Finger 8 on TV channels till 6th August. It was after four days of the scuffle , that the media gave another news that four officers and six jawans were released by the Chinese. Till now none of the details about casualties has been certified by the Army H/Q or by the government. What pained most the people of India was the timidity shown by the Prime Minister in not blaming China by name till now. He always referred China indirectly by using the expression "Those who". So on 20th June the govt closed this serious issue by saying that disengagement process would be taken up by Commander level talks.

Prime Minister visited Ladakh on 30th July and delivered a thundering speech saying era of expansionism was over. Even now, he did not accuse China by name. This shows the rhetorical speech was only meant for domestic consumption and image making after making disastrous statement on 19th.The decision to stop Chinese Apps was also a minor cosmetic surgery as nothing else was done to stop the import of the Chinese goods. A campaign against Chinese goods on the lines of famous campaign against British goods during 1905 national movement against partition of Bengal could have brought China to its knees. A little campaign raised against Chinese goods was soon hushed up after the talks of Ajit Dowal with Chinese Forein Minister. It only means that Chinese laid the pre -condition of stopping campaign against Chinese goods for holding further talks.

The final round of talks began on 2nd of August. The talks continued for eleven hours. Chinese commanders told that they would not withdraw further till Indian forces moved by 2kms as agreed already. Ajit Dowal held another meeting with army commanders and others to chalk out further strategy to make Chinese Army withdraw to April 20th position. We thought that something bold announcement would come out this time. It was stated that further efforts would be made to achieve the objective through diplomatic channels. Home Minister and General Rawat the CDS were not visible till now. News appeared that

Chinese forces are concentrating at other points along the border like Lipulekh Pass in Uttrakhand. They have also laid claim on Saktand Wild Life sanctuary in Bhutan.

A bombshell of information burst on 7th August in print media. A secret 4 page report of Defense Ministry was uploaded on its website and then withdrawn on 6th.The reasons for withdrawal were not given by the Ministry nor questioned by the godi media. The report says, "The Chinese side has transgressed in the areas of Kungrang Nala(patrol point 15 north of Hot Springs), Gogra(patrol point 17-A) and North bank of Pangog Tso on May 17-18.The situation in eastern Ladakh arising out of unilateral aggression by China continues to be sensitive and requires close monitoring and prompt action based upon evolving situation. The engagement and dialogue at military and diplomatic levels continues to arrive at a mutually acceptable consensus and the present stand off is likely to be prolonged. " This is what the Chinese want as they are already sitting pretty and looking at our haplessness. This is also the first admission of the fact of Chinese agression on Indian soil. Prime Minister wants the nation to believe that it was the victory of Indian Army on 15th June because our soldiers killed 40 soldiers of theirs.

The Prime Minister has either a soft corner for Xi or mortally frightened of China to push them back or he still hopes to win back the love of Xi. Xi has not uttered a word on this standoff with India so far. All the talking is done by the spokesperson. The swiftness of taking action against Pakistan is totally missing here. Collaborative media is not questioning or highlighting his timidity.

Now the Prime Minister is keen to prolong talks on disengagement and create a no war no peace situation so that public is gradually reconciled to the new situation and his own public image remains intact. A disspirited Opposition is also totally silent against Chinese surgical strike. Only Rahul Gandhi dares to speak and tries to put Modi on the mat. But his predicament is that he is alone and secondly his criticism is not couched in an effective language.

Now no war no peace situation will prove very costly to India's tottering economy. India will be stationing five divisions in Ladakh. Maintenance of army in Ladakh with long harsh winters proves many times more than maintaining the same in plains. The electricity has to be produced from disiel generators and huge amount of diesel oil has to be transported. Chinese are sitting pretty happy in our acclaimed territory. They dared to transgress the buffer zone because we let them off the hook in Doklam. Now China is further emboldened to engulf more territories because we have let them off the hook more timidly and easily than in Doklam. Now only God will save India from Chinese onslaughts. Now it is a pathetic scene when our generals and diplomats begging the Chinese to pull back.

In the end, I am reminded of Firaq Jalalpuri's couplet:

Tu idhar udhar ki baat na kar,
Tu ye bata kafila kyon loota,
Mujhe rahgiron se gila nahin,
Teri rehbari ka swaal hai.

खेल ग्रेडेशन नीति-2018 में संशोधन किया जाये

– डॉ. मलिक

भारतीय हाकी संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जाट सभा चंडीगढ़ के प्रधान– हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा. एम एस मलिक, आईपीएस (सेवानिवृत) ने हरियाणा सरकार की खेल ग्रेडेशन नीति–2018 का आंकलन करते हुए कहा कि यह खेल नीति प्रदेश के खिलाड़ियों के हितों व रोजगार उपलब्ध करवाने में लाभदायक नहीं है। इस नीति के अनुसार खेलों की ग्रेडेशन। पद कम लगभग 98 प्रतिशत कम हो जायेगा जिससे प्रदेश में खिलाड़ियों में बेरोजगारी बढ़ जायेगी।

डा. मलिक ने आगे कहा कि सरकार की नई खेल नीति के अनुसार जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्प्रधाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों व यहां तक कि जिला स्तरीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेडेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा और 30 नवंबर 1993 की खेल नीति की अपेक्षा नई खेल नीति में संपूर्ण ग्रेडेशन लगभग शून्य हो गया है। इसलिये खेलों के प्रोत्साहन व खिलाड़ी वर्ग के कल्याण हेतु सरकार की वर्ष 2018 की खेल नीति में आवश्यक संशोधन/सुझाव शामिल किये जाने अत्यंत आवश्यक हैं जैसा किः– खेल संघों, शिक्षा विभाग, खेल विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के लिये सभी आयु वर्गों के जुनियर व सब–जुनियर खिलाड़ियों को प्रतियोगिता अनुसार सीनियर के बराबर ग्रेड दिया जाये। वर्ष 2014 से लेकर अब तक के सभी अंर्तराष्ट्रीय पदक विजेताओं को नौकरी दी जानी चाहिए। नौकरी के लिये सभी वर्गों में ग्रेड अनुसार क, ख, ग वर्ग में वरीयता अंक दिये जायें। सर्विस केवल वरिष्ठ स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में ही नहीं बल्कि नौकरी के लिये निर्धारित आयु पूरी होने पर सब जुनियर व जूनियर खिलाड़ी भी प्राप्त ग्रेड के अनुसार सर्विस के लिये पात्र होने चाहिए।

धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह सर्वश्रेष्ठ है। -वेद व्यास

उपरोक्त के इलावा ग्रेड के लिये किसी खिलाड़ी के 50 प्रतिशत खेलने की शर्त, व्यक्तिगत व टीम गेम को अलग–अलग सुचियों में बांटना, खेलों में जातीय आधार पर आरक्षण देना आदि दोषपूर्ण नियमों को बदला जाये। केंद्रीय सरकार की तर्ज पर अंर्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तुरंत कैश इनाम देने का प्रावधान किया जाये। खिलाड़ियों के सर्विस पदक उपलब्धि के आधार पर दी जानी चाहिए ना कि टैस्ट के आधार पर/शिक्षण व खेल प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश खिलाड़ियों की वरीयता अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए। खेल कोटे से भर्ती खिलाड़ियों के प्रमोशन का विशेष प्रावधान होना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थाओं में आठवीं कक्षा से लेकर प्रवेश के लिये खिलाड़ी वर्ग के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया जाना चाहिए और सभी स्कूल व कालेजों में खेल आवश्यक किये जाने चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में खेलों के लिये 406. 17 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया था जोकि वर्ष 2020–20 से घटाकर 394.09 करोड़ कर दिया गया। अतः खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु स्वास्थ्य विभाग के बजट की तर्ज पर खेलों के लिये बजट भी हर वर्ष बढ़ाकर निर्धारित किया जाना चाहिए।

डा. मलिक ने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धि का बखान करते हुए कहा कि हरियाणा के युवा व मेहनतकश खिलाड़ी हर वर्ष राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिर्स्पधाओं में पदक जीत कर राष्ट्र की आन–मान को रोशन करते हैं इसलिये प्रदेश सरकार को प्रांत के खिलाड़ियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करते हुए खेलों के विस्तार के लिये खेलों को केंद्र की कनंकरैत सूची में शामिल करने के लिये केंद्रीय सरकार से आग्रह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व कल्याण हेतु सरकार द्वारा स्थाई तौर के कारगर नीति बनाई जानी चाहिए। जाट सभा द्वारा उपरोक्त सुझावों/संशोधनों को प्रदेश सरकार की नई खेल ग्रेडेशन नीति में शामिल करने हेतु हरियाणा के खेल राज्य मंत्री, निदेशक खेल व यूथ अफेयर हरियाणा व अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल व यूथ अफेयर हरियाणा को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है ताकि खेल व खिलाड़ियों को कल्याण हेतु लाभकारी व प्रभावशाली नीति सुनिश्चित की जा सके।

तीन कृषि अध्यादेश किसान हितैषी नहीं – डॉ0 लाठर

– डॉ० वीरेन्द्र सिंह लाठर

कोरोना आपदा लाकडाउन में चुपके से लागू किए तीन कृषि अध्यादेश, भारतीय किसान के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगगे क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में कम्पनी राज स्थापित करेंगे और किसान को बन्धुआ मजदूर बनाएगें। जैसा निम्नलिखित तथ्यों से साबित होता हैः–

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) 2020 से किसान को कोई लाभ नहीं होगा। लाभ केवल जमाखोरी और काला बाजारी करने वाले व्यापारियों और कम्पनियों को होगा, जो किसान से सस्ता कृषि उपज/उत्पाद खरीद कर, जमाखोरी और कालाबाजारी करेंगे और देश में कृत्रिम अभाव बना कर, कई गुना महंगा उत्पाद बेच कर उपभोक्ताओं को खुलमखुला लूटेंगे।

2. कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन और सुविधा) अध यादेश 2020 में दी गई सुविधाएं (बिना मण्डी फीस दिए–कृषि उपज मंडी अधिनियम कंट्रोल से मुक्त व्यापार) कभी किसान हितैषी नहीं होगा बल्कि केवल व्यापारियों और कम्पनियों के हितेषी होगा।

जब उन्हें बिना सरकारी कंट्रोल – मण्डी फीस और समर्थन मूल्य दिये, कृषि उपज खरीदने की खुली छूट मिल गई है, तब कृषि उपज मंडी सिर्फ सरकारी खरीद के लिए रहेंगगी जो आज देश के कुल कृषि उपज उत्पाद का मात्र 6 प्रतिशत है और बाकी 94 प्रतिशत कृषि उत्पाद समर्थन मूल्य से आधे दाम पर बिचौलिए और व्यापारी खरीदेंगे जैसा वर्ष 2006 से बिहार में हो रहा है। जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान होगा और राज्य सरकारों की कृषि वाणिज्य कर में भारी कमी होगी। जिसके प्रभाव से कृषि मंडियां व्यापार नहीं मिलने से अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगी तब आज का आत्मनिर्भर किसान पूरी तरह से भ्रष्ट बिचोलियों, व्यापारियों और कम्पनी राज पर निर्भर होकर मात्र एक बन्धुआ मजदूर बन जाएगा। इसलिए देश से कम्पनी राज भगाओं– किसान बचाओं अभियान जरूरी है क्योंकि किसान की सच्ची आजादी किसान के आत्म निर्भर रहने में ही है।

3. मूल्य आश्वासन पर (बन्दीबस्ती और सुरक्षा) समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020, बिना समर्थन मूल्य कानून बनाए कभी किसान हितैषी नहीं बन सकता क्योंकि कम्पनी राज के मुकाबले 82 प्रतिशत सीमांत भारतीय किसान (2 हेक्टेयर जोत से कम का किसान) आर्थिक, समाजिक, कानूनी तौर कभी भी अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे जैसा पिछले साल पेप्सी कम्पनी द्वारा गुजरात के आलू किसानों पर दर्ज किए मुकदमों से प्रमाणित भी हो चुका है। इसलिए, सरकार किसान विरोधी अध्यादेशों को बिना शर्त वापिस ले और किसान हितैषी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून अध यादेश लागू करे जिसे केन्द्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग ने खरीफ–2018 की रिपोर्ट में अनुमादित किया है। जिससे एक देश – फसल के एक न्यूनतम दाम का सिद्धान्त लागू होगा, किसान की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेंगी और फसल विविधीकरण में भी फायदा होगा जिससे देश तिलहन और दलहन में फायदा होगा जिससे देश तिलहन और दलहन में आत्म–निर्भर बनेगा।

मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और मिथ्या भाषण को सत्य से जीत सकता है। –गौतम बुद्ध

किसान को धर्म व जाति में बांटने की साजिश

– के.पी. मलिक

बड़े बुजुर्ग बताते है कि आपदा अपने साथ अवसर लेकर आती है। सत्ता षड्यंत्रों में कामयाब होती है तो अपने लिए अवसर में तब्दील कर लेती है और जनता जागरूक व लड़ाकू होती है तो स्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेती है। यहाँ पर में मध्य प्रदेश के जिले गुना के हुई बर्बरता पूर्ण घटना 'आपदा को अवसर' में तब्दील करेन वाली दिखाई पड़ती है। जहां देश वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के महम लॉकडाउन से जूझ रहा है वहीं है सरकार अपने एंजेंडे पर लगातार काम कर रही है मेरा सवाल है कि क्या यहां केवल लोगों के लिए ही तालाबंदी है ? सरकार के लिए नहीं ? किसान से जमीन खाली कराना क्या किसी इमरजेंसी सेवाओं में आता है।? अगर बाकी सभी काम रोक दिए गए हैं तो फसल को उजाड़ने के लिए आदेश किसने और किसके दबाव में दिए ? तो क्या माना जाये कि सत्ता इस आपदा को अवसर में तब्दील करती नजर आ रही है। सरकारों क्यां नहीं नियम का पालन कर रही है।

भोपाल से सटे गुना में एक गरीब किसान के साथ पुलिस की बर्बरता पूर्ण पिटाई की इस घटना के वायरल वीडियों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ बर्बाद होते देख उस असहाय किसान परिवार पर नेताओं की कठपुतली पुलिस बेहरमी से लाठी बरसा रही थी। तस्वीरें सामने आने के बाद प्रदेश में हंगामा मचा तो शिवराज सरकार की नींद खुली और सरकार ने खानापूर्ति करते हुए वही रटा रटाया आदेश दे दिया जिसमें सरकार ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकक को हटा दिया है। क्या इससे किसान की समस्या का समाधान हो गया या किसान को कुछ राहत मिल गई ?

सोशल मीडिया पर गुना के किसान परिवार की रोतीं तस्वीरें किसान हितैषी होने का दंभ भरने, किसानों के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले तमाम किसान संगठनों तमाम राजनीतिक दलो के किसान नेताओं से पूछ रही है कि एक किसान के साथ प्रशासन किस तरह का व्यवहार कर रहा है। यहां मैं बिना वजह किसान तरफदारी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर किसान कहीं गलत था भी ? तो उस मामले को किसान और प्रशासन बैठकर सुलझाए जाने की आवश्यकता थी। उसमें वहां के स्थानीय किसान संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ना ही किसान संगठनों और ना ही सरकार में बैइे किसान प्रतिनिधियों को फुर्सत है क्योंकि सब अपने दलाली भट्टे में व्यस्त और मस्त हैं और किसान यहां पूंजीवादियों के दमन चक्र में पिसता जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि नेताओं, सरकार और पत्रकारों ने किसानों को धर्म और जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। देश के कई मुख्य मीडिया समूह के समाचार पत्रों ने किसान को दलित बताने या दलित लिखने में अखबारों समाचार पत्रों का क्या उद्देश्य हैं? या क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है? यह जानना किसानों और तमाम लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि तथाकथित किसान नेताओं एवं राजनीतिक दलों के किसान नेताओं का इस रणनीति के पीछे क्या उद्देश्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह एक किसान है तो उसककी जाति बताना क्यों जरूरी है ? क्या यह बताना जरूरी है कि वह दलित है ? क्या उसका धर्म और उसकी जाति, समुदाय, क्षेत्र, पंत आदि बताने का औचित्य क्या है ? इस विषय पर किसानों और किसानों के हितेषियों को तत्काल विचार विमर्श करने एवं सोचने की आवश्यकता है क्योंकि ये राजनैतिक दलों के तथाकथित किसान नेता आम किसानों को जातियों, धर्मों, क्षेत्रों, समुदायों आदि में बांट ककर बर्बाद करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए है। मैं तो कहता हूँ किि अगर किसान जल्दी नहीं जागा तो उसको धर्म, समुदाय, जाति और क्षेत्र के नाम पर तो बाट ही चुके अब उसको फसलों के हिसाब से बांटने ककी तैयारी चल रही है। जैसे यह धान का किसान, यह गन्ने का किसान, यह बाजरे का किसान, यह मक्का का किसान, यह ज्वार का किसान आदि इस प्रकार किसानों को अलग–अलग बांटकर किसान की कमर तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। किसान को बर्बाद करने के लिए तथाकथित किसान नेता अपनी दुकानें चलाने के लिए लगातार पूंजीवादियों और सरकार का साथ दे रहे हैं यह किसी से छूपा हुआ नहीं है।

हैरत की बात है कि दलितों के लिए कुर्बानी देने और दलितों की लड़ाई लड़ने वाला राजनीतिक दल बसपा की सुप्रीमो मायावती ने घटना की निंदा करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रस्म अदायगी कर दी है। लेख लिखे जाने तक मुझे किसी किसान संगठन या किसाना की हक की लड़ाई लड़ने वाले तथाकथित किसान ली है अब कर्ज में डूब चुका हूं। लेकिन पुलिस जमीन को खाली कराने पर अड़ी रही और लगातार जमीन को खाली कराने के लिए दबाव डाला जा रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल वीडियों में इस तरह की दर्दनाक और बर्बरता पूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं। जिससे पुलिस की बर्बरता और गरीब किसान परिवार की बात सुनने को तैयार नहीं दिखाई देना पुलिस की मानसिकता को दर्शाता है। जबकि राजकमार का कहना था कि ये उसकी पैतुक जमीन है। दादा–परदादा इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। हो लेकिन यह भी सही है कि उसके पास पट्टा नहीं है। जब जमीन खाली पड़ी थी तो उस समय कोई क्यों नहीं आया ? अब जब दो लाख रुपये का कर्ज लेकर फसल की बुआई कर दी और अब फसल अंकुरित हो गई तो इस पर बुल्डोजर चलाने आ गए। मेरे परिवार में दस से बारह इसी खेती खेती पर आधारित है और अपनी गुजर–बसर करते हैं। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो लिहाजा मैं आत्महत्या करूंगा। ये कह कर उसने खेतों में प्रयोग हासेने वाला कीटनाशक पी लिया और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी कीटनाशक पी लिया जिसकी वजह से वह तुरंत बेहोश हो गया और पुलिस किसी तरह उसको खींचते हुए स्थानीय अस्पताल ले गई जहां पर वह पति–पत्नी अभी जिदंगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे है।

जो मनुष्य अपने मन का गुलाम बना रहता है, वह कभी नेता और प्रभावशाली पुरुष नहीं हो सकता। –स्वेटमर्डिन

बेमिसाल साहसी और अद्वितीय क्रांतिकारी मदनलाल ढिंगडा को शहादत दिवस पर नमन

– एडवोकेट रघुबीर सिंह दहिया, रोहतक

आम जनता शहादतों की अपनी बेमिसाल विरासत को सदा ही पूरे आदर और सम्मान के साथ याद करती है। इसके विपरित शोषक भय से कांपने लगते हैं। बेचौनी में शोषक वर्ग महान देशभक्त क्रांतिकारी शहीदों के विचारों का इतिहास विस्मृति की मैली चादर से ढांपने की लगातार कुचेष्टा करते हैं। झूठ से सनी हुई .तघ्नता की नुगरी चालें कीचड में डुबो देती हैं वहीं एक इंसान अपने आदर्श के फर्ज की चाहत में वंदे मातरम बोलता हुआ फांसी के तख्ते पर चढकर शहीद हो जाता है। शोषक ताकत का इस्तेमाल करता है, दमन और उत्पीडन के असहनीय जख्म देने के लिए जबकि शोषित की ताकत दमन को सहन करती है और उसकी समझ से शोषक को उखाड फेंकती है। एक महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगडा ने लंदन में कर्जन वायली को गोलियों से भूनकर दुनिया से चलता कर दिया। 17 अगस्त 1909 को इस अद्वितीय साहसी को लंदन की पेंटोन्विली जेल में फांसी पर लटकाकर उनके शव को चुपचाप वहीं पर दफना भी दिया गया। उनका बलिदान अमर है और उन्होंने इंसानी फर्ज से एक उच्च क्रांतिकारी आदर्श स्थापित किया, जो आने वाली पीढियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया।

मदनलाल ढींगडा का जन्म आठ फरवरी 1887 को अमृतसर पंजाब में एक अति संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता डॉ. दित्तामल पंजाब में सिविल सर्जन थे और उनकी मां मंतो दीव प्रतिभा संपन्न आदर्श महिला थी। मदनलाल ढींगडा के छह भाई और एक बहन थी। सबसे बडा भाई कुंदन लाल ढींगडा प्रसिद्ध बडा कपडा व्यापारी था और दूसरा भाई मोहनलाल ढींगडा ब्रिटेन में पढाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बन चुका था। तीसरा भाई बिहारी लाल भी वहीं से पढा और डॉक्टर बना। चौथा भाई चमनलाल बेरिस्टर बना और पांचवां भाई न्यायाधीश बना। छठे नंबर पर आने वाले स्वयं मदनलाल ढींगडा 1906 में इंजीनियरिंग की पढाई के लिए लंदन इंग्लैंड गए और पूरे परिवार का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज करवाकर 22 वर्ष की उम्र में आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढकर शहीद हो गए। सबसे छोटा भाई भजनलाल वकील बना। मदनलाल ढींगडा की बहन काकी रानी का विवाहर बडे भूस्वामी के साथ हुआ था और इस तरह मदनलाल ढींगडा के परिवार सुशिक्षित और संपन्न था।

मदनलाल ढींगडा का दाखिला अमृतसर के जाने माने मिशन स्कूल में करवाया गया। स्कूल की शिक्षा के बाद उन्होंने अमृतसर के एक कॉलेज में दाखिला लिया तो देश की वास्तविकता समझ में आने लगी, जबकि उनके पिता राय साहब डॉ. दित्तामल कट्टर अंग्रेज भक्त थे। अपने पिता से विपरित मदनलाल की प्र.ति परिवार से अलग थी और वे अंग्रेज शासकों को नफरत की .ष्टि से देखते थे। इस प्रकार की परिस्थितियों को समझकर पिता डॉ. दित्तामल ने अपने पुत्र मदनलाल को अमृतसर के कॉलेज से निकालकर लाहौर के गर्वनमेंट कॉलेज में दाखिला करवाया ताकि पढाई लिखाई का वातावरण बदल जाए और मदनलाल की सोच यानी अंग्रेज सरकार के प्रति राजभक्ति के भावों का प्रदर्शन करे।

लाहौर कॉलेज में पढते हुए मदनलाल की मुलाकात एक उदारवादी रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ओ ब्राउंन से हुई। उन्होंने मदनलाल की प्रतिभा को समझकर उन्हें पढने के लिए प्रेरित किया और विद्वान बनने की सलाह देते हुए कहा, ज्ञान और साहस की प्रतिभा दुनिया को बदल सकती है। पहले पढाई करते हुए अपने विवेक से समझो और फिर ब्रिटिश साम्राज्य की जडों पर पूरी ताकत से प्रहार करो। विशाल साम्राज्य जिसमें सूरज नहीं डूबता, सूख जाएगा। पिता डॉ. दित्तामल ने पुत्र मदनलाल को पढाई छोडकर वापस अमृतसर बुलाया लेकिन पुत्र ने वापस अमृतसर आने से इंकार कर दिया और लाहौर में अपनी पढाई जारी रखी। नाराज पिता ने खर्च भेजना बंद कर दिया तो मजबूरन अमृतसर ही आना पडा और बडे भाई कुंदनलाल के साथ कपडे का व्यापार करने लगे। व्यापार में मन तो लगना ही नहीं था इसलिए पिता ने आर्थिक मदद देनी चाही लेकिन साफ इंकार कर दिया। अपने बडे भाई से लाहौर जाकर पढने की इजाजत मांगी तो भाइयों ने पिता से बात कर मदनलालल को फिर से पढने के लिए लाहौर भेज दिया। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी से मदनलाल ढींगडा ने स्नातक की।

मां की इच्छा पर मदनलाल ने 1905 में विवाह कर लिया लेकिन इंग्लैंड जाकर पढाई करने की इच्छा बलवती हो रही थी और जुलाई 1906 में समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचकर अपने बडे भाई कुंदनलाल के पास रहने लगे। बडे भाई के प्रयास से मदनलाल को 14 अक्टूबर 1906 को लंदन के एक

इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला और पढाई शुरू हो गई। एक दिन लंदन में घूमते हुए मदनलाल ढींगडा को इंडिया हाउस की बिल्डिंग दिखाई दी तो वहां श्याम जी .ष्ण वर्मा से मिले, जो इंडिया हाउस के संस्स्थापक थे। वे क्रांतिकारियों का तहेदिल से आदर सम्मान करते थे। मदनलाल ने उनसे बातचीत की और पहली ही मुलाकात में उनके महान व्यक्तित्व में अंग्रेजों के राज के प्रति साक्षात घृणा देखी। वे लंदन में पढने वाले भारतीय विद्यार्थियों में देशप्रेम की भावना जागृत कर ब्रिटिश सामाज्य की जडे उखाड फेंकने के लिए प्रेरित करते थे। मदनलाल ढींगढा उनसे काफी प्रभावित हुए और फिर तो इंडिया हाउस रोज का आना जाना होने लगा। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह की जन्मशती के अवसर पर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय इंग्लैंड आए तो उन्होंने लंदन के इंडिया हाउस में भारतीय छात्रों को संबोधित किया। वहां पर मदनलाल भी उन्हें सुन रहे थे। लाला जी के राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कार्यक्रम के बाद लाला लाजपत राय से लंबी बातचीत की। लाला लाजपतराय ने उन्हें पहले अपनी पढाई पूरी करने की सलाह दी और लालाजी के भाषण से प्रभावित होकर मदनलाल ढींगडा रिवाल्वर चलाने का अभ्यास करने लगे। मदनलाल ने मन ही मन ये विचार किया कि उनके पिता अंग्रेजों के भक्त हैं और पूरी तरह से उनके वफादार हैं। वे अंग्रेजों शाषकों से दोस्ती करना गर्व समझते हैं। ऐसे भारतीय ही अंग्रेजी साम्राज्य की जडें भारत भूमि पर जमाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और सरकार अपने व्यापक हितों के लिए इन चापलूसों को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी करती है। मदनलाल की लंदन में जवाहरलाल नेहरू, सिकंदर हयात खां और सैफुद्दीन किचूल से भी मुलाकात हुई। वे भगतसिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों से अत्यंत प्रभावित हुए और उसे महान आदर्श के रूप में देखते थे। उस समय अंग्रेज सरकार ने तीन सदस्यों की एक समिति गठित की थी। ये समिति भारतीय छात्रों में अपने ही देश के लिए नफरत पैदा करने के प्रयास करती थी। सर कर्जन वायली इस समिति के सलाहकार थे। वायली एक चालाक, धूर्त, मक्कार, नुगरा व्यक्ति था। वह लंदन में भारत के सचिव का भी सलाहकार था। जो विद्यार्थी भारत की आजादी के लिए काम करते थे, वह उन्हें कडा दंड दिलवाता था, इसलिए भारतीय विद्यार्थी उसे घृणा की नजरों से देखते थे। मदनलाल ढींगडा ने मन ही मन उन्हें ठिकाने लगाने का निश्चय कर लिया था और अपनी इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंस्टीट्यूट आफ इंपीरियल स्टडीज के जहांगीर हाउस में इंडियन नेशनल एसोसिएशन के समारोह में कर्जन वायली ने भाग लिया। 11 बजे जब समारोह समाप्त हुआ तो लगभग 250 मेहमान मौजूद थे। मौका देखकर मदनलाल ढींगडा सर कर्जन वायली के ठीक सामने गए और दो गोलियों से उनका मुंह फाड दिया। इसके बाद दो गोलियां उनकी छाती पर चलाकर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसी दौरान एक भारतीय डॉ. लालका कायली को बचाने के लिए मदनलाल पर झपटा तो उस महान क्रांतिकारी ने उसे भी गोली मार दी। कायली के तो वहीं पर प्राण पखेरू उड गए लेकिन डा. लालका की मौत अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में हुई। जहांगीर हाल में अफरा तफरी मच गई और महान साहसी क्रांतिकारी मदनलाल ढींगडा को पुलिस ने गिरतार कर लिया। डॉक्टरी चेकअप के दौरान उनकी नब्ज तो सामान्य थी लेकिन जांच करने वाला डॉक्टर कांप रहा था। मदनलाल उनकी हालत देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद अद्वितीय साहसी मदनलाल ढींगडा का नाम पूरी दुनिया को पता चल गया। भारत समेत पूरी दुनिया के क्रांतिकारी संगठनों में आशा की लहर दौड गई लेकिन अंग्रेज भक्त डॉ. दित्तामल ने मदनलाल अपना पुत्र मानने से ही इंकार कर दिया। लंदन के कैक्स्टन हाल में पांच जुलाई 1909 को अंग्रेज सरकार के प्रति उदार भारतीय ढींगडा के इस महान कार्य की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे लेकिन सावरकार ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया। इस पर एक अंग्रेज ने सावरकर के मुंह पर घूंसा मारा तो वहीं पर मौजूद एक दूसरे साहसी भारतीय युवक ने अंग्रेज युवक एडवर्ड पामर केसिर के सिर पर डंडा मारकर हिसाब बराबर कर दिया। सभा में अव्यवस्था होने पर बिना प्रस्ताव पास ही सभा खत्म हो गई। इतना ही नहीं वीर सावरकर ने छह जुलाई को एक अखबार में पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि न्यायालय ने उसे दोषी करार नहीं दिया है। जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक प्रस्ताव में मदनलाल को अपराधी की संज्ञा न दी जाए। सरोजनी नायडू के भाई वीरेंद्रनाथ ने मदनलाल ढींगडा के कार्य को देशभक्ति और महानता का काम बताया, जबकि मदनलाल ढींगडा के पिता डॉ. दित्तामल ने अंग्रेज अधिकारियों को लिखा कि, अंग्रेज सरकार के प्रति उनकी निष्ठा पर शक ना किया जाए। मदनलाल तो बचपन से ही मानसिक रूप से सनकी और असंतुलित था। उस घटना के बाद इंडिया हाउस को बंद कर दिया गया और छात्रों की गतिविधियों के केंद्र श्याम .ष्ण वर्मा ने उस भवन को बेच दिया और मदनलाल के काम की प्रशंसा की। 10 जुलाई 1909 को उसे अदालत में पेश किया गया। परिवार ने भरसक प्रयास किया कि कोर्ट में संदेह का आभास आधार बन जाए कि मदनलाल एक मानसिक रूप

जो मनुष्य अपने मन का गुलाम बना रहता है, वह कभी नेता और प्रभावशाली पुरुष नहीं हो सकता। –स्वेटमर्डिन

से अंसतुलित युवक है। इसके विपरित चिकित्सक ने उसे अत्यंत संतुलित बताया। वायली की सचिव ऐमा जोसेफ बैक ने मदनलाल का बचाव किया। कॉलेज के दो प्रोफेसर ने भी मदनलाल के चरित्र की पूरी सराहना की। पुलिस ने अनेक साक्ष्य अदालत के सामने रखे। मदन मोहन सिन्हा और पत्रकार डगलस थॉरबोर्न को पुलिस ने गवाह के रूप में पेश किया और दोनों ने मदनलाल के खिलाफ गवाही दी। देशभक्त ढींगडा ने अदालत में कहा कि–मैं स्वीकार करता हूं मैंने कर्जन वायली की हत्या सोच समझकर की है। भारतीय युवकों को फांसी देने और काले पानी भेजने के अमानवीय यातनाओं का प्रतिशोध लेने के लिए ये कत्ल किया है। अंग्रेस सरकार की अदालत का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद न्याय का गला घोंटकर अदालत ने न्याय का ड्रामा बनाया। 23 जुलाई 1919 को फांसी की सजा सुनाई गई और महज दस दिन की कार्रवाई अदालत में चली। 17 अगस्त 1909 को फांसी की तिथि मुकर्रर की गई। सुनवाई के दौरान मदनलाल ने कोर्ट में दो ऐतिहासिक बयान दिए थे। मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने का अंग्रेज सरकार को कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेजों ने मेरे देश को गुलाम बनाकर निर्मम शोषण किया है और लगभग आठ करोड भारतीयों को डेढ सौ साल में मौत के घाट उतारा है। सौ मिलियन डॉलर का धन भारत से लूटकर ब्रिटेन में लाया गया है और आजादी की मांग करने वालों को फांसी पर चढाया जा रहा है। देश की जनता के सूखे शरी से खून निचोडकर बेरहमी से शोषण करने की ब्रिटिश सरकार अपराधी है। अंग्रेज सरकार कांगो और रूस में मानवता के हनन की बातें करती है जबकि भारत के लाखों लोगों को मानव अधिकारों की रक्षा के बहाने मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। ब्रिटेन को अपने कब्जे में लेने की नीयत से आए जर्मन को गोली से मार देने पर आप ब्रिटेन को नागरिक को देशभक्त मानते हो लेकिन जब मैं अंग्रेज को गोली मारता हूं तो मुझे देशभक्त की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता? 17 अगस्त 1909 को भारत के महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगडा को लंदन की पेन्टोन्विली जेल में फांसी के तख्ते पर चढा दिया गया। वंदे मातरम बोलते हुए वो फांसी के तख्ते पर झूल गए। उन जैसे वीरों की शहादत से 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। उनकी शहादत के 67 वर्ष बाद 1976 में उनके अवशेष कब्र से निकाले गए और 67 वर्ष बाद भारत के इस महान सबूत के अवशेषों को 13 दिसंबर 1976 को पालम हवाई अड्डे पर देश की धरती पर पहुंचने का अवसर मिला। 25 दिसंबर को उनके अवशेषों को सम्मान अमृतसर में भारत की धरती मां की गोद नसीब हुई। ऐसे महान वीर क्रांतिकारी योद्धा के शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन है।

स्वतंत्रता और विभाजन का हरियाणा की राजनीति पर प्रभाव

– प्रोफेसर रणबीर सिंह, करनाल

1952 में हुए चुनावों का हरियाणा की राजनीति पर गहन प्रभाव पड़ा। लोकसभा की इस क्षेत्र में निर्धारित सभी सातों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते। कांग्रेस की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व की वजह से यह जीत संभव हो पाई थी। विधानसभा की भी 45 सीटों में से 42 भी इसी दल ने जीती। जमींदारा लीग का जनाधार केवल जाटों तक सिमटने के कारण दो ही सीटों पर चुनाव जीत हासिल कर सकी। बहादुरगढ़ से चौधरी श्रीचंद और सांपला से चौधरी माडू सिंह ही चुनाव जीत पाए। ये भी जाट बाहुल्य सीट होने की वजह से हो पाया था।

भारतीय जनसंघ भी शहरों में पंजाबी जनाधार पर सीमित थी इसलिए उसे एक भी स्थान पर जीत नहीं मिल सकी। एक सीट समाजवादी दल ने भी जीती। इसके प्रत्याशी रामप्रकाश जगाधरी की आरक्षित सीट से चुनाव जीते थे लेकिन इसमें उनकी पार्टी का कम और उनका व्यक्तिगत प्रभाव ज्यादा रहा था। इस चुनाव में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बुटाना करनाल में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जमानत भी जब्त करवा बैठे थे।

चुनाव में गुड़गांव से चुने गए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद केंद्र में शिक्षाामंत्री बने और उन्हीं की इच्छा से भीमसेन सच्चर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि तब विधायकों का बहुत प्रताप सिंह कैरो के साथ था। सच्चर ने हरियाणा क्षेत्र से रोहतक जिले के पंडित श्रीराम शर्मा और चौधरी लहरी सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। इसके बाद बदले राजनीतिक घटनाक्रम में अमृतसर से विधायक सतपाल सहगल गुट से टकराव के चलते पंडित श्रीराम शर्मा को 1953 में निकाल दिया गया। इसके बाद नाराज होकर उन्होंने कुछ अन्य नाराज कांग्रेसियों को लेकर गांधी जनता पार्टी का गठन किया। इस पार्टी में गोहाना के मास्टर नांदुराम, पटौदी के पंडित बाबू दयाल शर्मा और नूंह से मौलवी अब्दुल गनी शामिल हुए।

1953 में राज्य पुर्नगठन आयोग की स्थापना के बाद

गुस्से को शर्बत के घूंट की तरह पी जाओ, क्योंकि जहां तक उसके अंत का संबंध है, इससे अच्छी और कोई आनंददायक वस्तु नहीं है। –अज्ञात

पंडित श्रीराम शर्मा ने गांधी जनता पार्टी, जमींदारा लीग और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर हरियाणा प्रांत फ्रंट बनाया और अलग राज्य की आवाज बुलंद की। फ्रंट का कहना था कि हरियाणा की भाषा और संस्.ति पूरी तरह से पंजाब से अलग है और दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर हरियाणा से मिलते हैं। हरियाणा के नेताओं की इस मांग का अकाली दल ने भी समर्थन किया।

कैरो खेमे के कांग्रेसी विधायक चौधरी देवीलाल, बाबू मूलचंद जैन और प्रोफेसर शेरसिंह ने भी इस मांग के पत्र में आवाज उठाई थी लेकिन जनसंघ ने इसका विरोध किया। एक तरफ जहां चौधरी देवीलाल ने इसे भाषाई और सांस्. तिक आधार पर उठाया वहीं प्रोफेसर शेरसिंह ने हरियाणा की विकास में अनदेखी, मंत्रिमंडल और सरदारी पदों में भागीदारी नहीं मिलने की बात उठाई और अलग हरियाणा का समर्थन किया।

हरियाणा प्रांत फ्रंट ने समालखा, सोनीपत और रोहतक में इस मांग के समर्थन में सम्मेलन किए पर कोई बड़ा जनआंदोलन उस वक्त खड़ा नहीं हो सका था। इसके समर्थक विधायकों ने विधानसभा में भी ये आवाज उठाई। हरियाणा के स्थानीय लोगों विशेषकर जाटों का इस मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिला। हरियाणा के पंजाबियों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि किसी भी सूरत में पंजाब का एक और विभाजन नहीं हो। जनसंघ ने तो अलग पंजाबी सूबे की मांग के विरोध में यह मांग उठाई की पेप्सू और हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब में मिलाना चाहिए।

आयोग ने हरयिाणा प्रांत की मांग को यह कहकर रद कर दिया कि इस घाटे वाले क्षेत्र को अलग राज्य बनाने से इसकी वास्तविक और काल्पनिक शिकायतों को दूर नहीं किया जा सकता है। आयोग ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि दिल्ली की विधानसभा ने सर्वसम्मति से महादिल्ली के गठन के लिए पंजाब के हरियाणा क्षेत्र, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ भाग दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 विधायकों ने भी इसके पक्ष ज्ञापन दिया था। पंडित नेहरू भी पंजाबी सूबे की मांग और यूपी के विभाजन के पक्ष में नहीं थे इसलिए आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया था।

कैरों समर्थकों के दबाव में 1956 में भीमसेन सच्चर को त्यागपत्र देना पडा और कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह को उप मुख्यमंत्री और मूलचंद जैन को मंत्री बनाया। चौधरी देवीलाल को मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया। इस राजनीतिक बदलाव में हरियाणा के विधायकों की अहम भूमिका रही।

पंजाबी सूबे की मांग के न माने जाने के बाद अकालियों को शांत करवाने के लिए और हरियाणा प्रांत फ्रंट को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय फार्मूला बनाया गया। पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में बांटा गया। दोनों के लिए क्षेत्रीय समितियां बनाई गई। 1956 में पेप्सु के पंजाब में विलय के बाद वहां के मुख्यमंत्री ब्रिशभान को उप मुख्यमंत्री और वहां की मुख्य संसदीय सचिव चंद्रावती को संसदीय सचिव बनाया गया था।

आओ याद करें गौभक्त, शिक्षा प्रेमी भगत फूल के योगदान को

– धर्मेंद्र कंवारी, रोहतक

24 फरवरी 1885 को सोनीपत के पास माहरा गांव में एक किसान परिवार में बच्चा जन्मा। पढाई में होशियार वह बच्चा किशोर बनते ही 19 साल की उम्र में ही पटवारी भी नियुक्त हो गया। अब भले ही पटवारी की कद्र ना हो लेकिन उस वक्त पटवारी होना अपने आप में कायदे आजम होना ही था। पटवारी बनने के बाद उन्होंने रिश्वत भी ली और तमाम व्यसन भीकरके देखे। एक दिन उनकी मुलाकात स्वामी सुबोधानंद से हुई और हरफूल सिंह पटवारी की जगह भगत फूल सिंह जैसी शख्सियत का जन्म हुआ। जिस पटवारी की आसपास के गांवों में तूती बोलती थी वह एक जमींदार के घर के सामने खडा होकर गिडगिडा रहा था कि–जमींदार मैंने तुझसे एक काम के लिए रिश्वत ली थी तूं मुझे दो कोडे मार दे ताकि मुझे प्राश्चित हो जाए।

कन्याओं के लिए अपनी ही जमीन दान कर पहला गुरुकुल खोलने की शुरुआत की। आर्थिक दिक्कतें आई तो एक दिन मंत्री चौधरी छोटूराम के दरवाजे पर लाहौर जा पहुंचे भगत फूल सिंह। दरबानों ने चौधरी साहब तक संदेश भिजवाया कि एक बाबा हरियाणा से उनसे मिलने आया है। चौधरी साहब ये कहकर बाहर दौडे की जरूर भगत फूल सिंह जी आए होंगे। उनका अंदाजा भी सही निकला और तब गुरुकुल में लाहौर से बिस्तर और तख्तों से भरी गाडी पहुंची थी। आज ये गुरुकुल विश्वविद्यालय बन चुका है।

एक दिन भगत फूल सिंह गुरुकुल के चंदे के लिए हाथ पसारे एक गांव में पहुंचे तो देखा कि कुएं पर दलित

जैसे गरुड़ को देखते ही सब सांप विषहीन हो जाते हैं, वैसे ही गंगाजी के दर्शन से मानव सब पापों से छुटकारा पा जाता है। –महाभारत

महिलाएं पानी के इंतजार में बैठी हैं। उस दिन की महिला ने उनके बर्तनों में पानी डालने की जहमत नहीं उठाई थी। भगतफूल सिंह वहीं अनशन पर बैठ गए। जल भी त्याग दिया। गांव वाले पुरानी परंपराएं त्यागने को तैयार नहीं थे और भगत फूल सिंह अपना हठ। चौधरी छोटूराम को किसी ने इसकी खबर दी। चौधरी साहब गांव में पहुंचे और कहा कि शाम तक गांव में नया कुंआ खोदो और उसका पानी मैं भगत जी को पिलाकर ही जाऊंगा। बात के धनी चौधरी साहब की सुनी गई और सबने मिलकर नया कुआं खोदा तब जाकर भगत फूल ने पानी पिया और परांपराएं भी पानी में बह गई।

14 अगस्त 1942 का दिन था। चौधरी छोटूराम को भगत फूल सिंह के पास गुरुकुल में आना था। चौधरी साहब उस दिन पहुंच नहीं सके और इसका टेलीग्राम भी उन्होंने भिजवा दिया था कि भगत जी व्यवस्तताओं के चलते मैं नहीं पहुंच सकूंगा आप लाहौर आने का कार्यक्रम बनाएं ताकि सारी बातें विस्तार से की जा सकें।

खैर टेलीग्राम समय पर नहीं पहुंचा लेकिन भगत फूल सिंह बार–बार गुरुकुल से बाहर निकलकर देखते रहे कि कहीं चौधरी साहब का काफिला आ तो नहीं रहा। तभी दूर से 15–20 घुडसवार आते दिखाई दिए। भगत फूल सिंह मन में फूले नहीं समा रहे थे। घुडसवार पास आए और तभी एक गोली सीधे उनकी छाती में आकर लगी। भगत फूल सिंह नफरत की गोली का शिकार हो गए और मरते–मरते उनके मुंह से यही निकला कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे सभी बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। इस मुहिम को रूकने मत देना। 14 अगस्त और भगत फूल सिंह का पुण्य स्मृति दिवस है। भगत फूल सिंह ने हरियाणा में बेटियों को शिक्षित करने की जो लौ जलाई थी वह आज भी अनवरत जारी है। ऐसी महान आत्मा की पुण्यतिथित पर हम उनको नमन करते हैं।

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl 31/5'4" M.A. English from P. U. Employed as regular English Teacher with Chandigarh Administration. Father officer retired from Haryana govt. Avoid Gotras: Malik, Kundu. Cont.: 7009239419, 9417093860
- SM4 Divorced Jat Girl 41/5'6" M.A., M.Phil, Ph.D. Employed as Assistant Professor in Government College Panchkula. Preferred class-I or highly status businessman. Father retired from Army. Avoid Gotras: Sheokand, Beriwal. Cont.: 9728612704, 9416556162
- SM4 Jat Girl (DOB 1988) 32/5'3" M.A. Eco, Ph.D. Eco., NET clear. Employed as Assistant Professor (Adhoc) in Chandigarh. Father class-II officer retired from Haryana government. Brother settled in USA. Avoid Gotras: Dahiya, Sehrawat, Jatrana. Cont.: 9988224040
- SM4 Jat Girl (DOB 10.08.93) 27/5'3" BCA. Avoid Gotras: Dhanda, Sharan, Beniwal. Cont.: 9023058463
- SM4 Jat Girl (DOB 15.12.88) 31/5'6" B.Sc. Biotech, M.Sc Biotech, Employed as Social Security Officer, RAS-Batch-2013 in Rajsthan Government. Father retired from Rajsthan government. Avoid Gotras: Jakhar, Kadian, Dhankhad. Cont.: 9928543649, 6376607068
- SM4 Jat Girl (DOB 22.12.96) 23/5'6" B.A. B.Ed. Employed as JBT regular. Avoid Gotras: Lohan, Punia, Goyat Cont.: 9465875228
- SM4 Jat Girl (DOB 04.12.90) 29/5'2" MCA. Employed in MNC at Mohali. Avoid Gotras: Gulia, Malhan, Dalal. Cont.: 9780385939
- SM4 Jat Girl (DOB 25.09.95) 24/ 5'2" M.Com. Avoid Gotras: Dulat, Datten, Sindher. Cont.: 9416071509, 9354766729
- SM4 Jat Girl (DOB 30.11.95) 24/5'5" B.A. Eng.(Hons.) from DU. MA. Eng. (Hons) from KU. M. Phil. Eng., Pursuing BE.d. from MDU. Father businessman. Mother Govt. teacher. Avoid Gotras: Saroha, Sehrawat, Mann. Cont.: 9899209912
- SM4 Jat Girl (DOB 17.09.92) 27/5'3" B.E. (Hons.) Civil, M.Sc (Hons.) Economics, BITS Pilani-2015, PGDM (Finance), IMI, New Delhi-2018, CFA (Chartered Financial Analyst) Level-I with Rs. 11.75 Lac PA. Father lawyer in Punjab & Haryana High Court, Mother class-I officer in Haryana Government. Avoid Gotras: Banger, Laura. Cont.: 9416886388
- SM4 Jat Girl 29/5'7" B. Tech, Civil from PEC Chandigarh. Employed as ETO in Government of Haryana. Preferred Class-I or II Officer of Govt. of Haryana, GOI Haryana Cadre/Zone. Father HCS (Rtd.). Avoid Gotras: Kairon, Damara, Mor. Cont.: 9467222000, 8360106972
- SM4 Jat Girl (DOB 23.08.91) 28.11/5'4" B. Tech, (Electric & Communication). Avoid Gotras: Pawaria, Ahlawat, Nandal. Cont.: 9996060345
- SM4 Jat Girl (DOB 31.05.87) 33/5'5" M.A. B.Ed, M.Ed. ETT, JBT. Employed as JBT Teacher in Punjab Govt. School. Father retired from PGI Chandigarh. Mother housewife. Avoid Gotras: Dabas, Dalal, Dhankar. Cont.: 9878353500, 9646963113
- SM4 Jat Girl (DOB 03.12.95) 24/5'5" B.A. Father retired from PGI Chandigarh. Mother housewife. Avoid Gotras:

Dabas, Dalal, Dhankar. Cont.: 9878353500, 9646963113

- SM4 Divorced issueless Jat Girl (DOB 12.05.88) 32/5'2" B.Sc. (MLT), M.Sc (Microbiology) from Punjab Technical University Jalandhar. Working as Lab Incharge in reputed Paras Hospital Sector 22, Panchkula. Father in Government job at Panchkula. Avoid Gotras: Mittan, Kharb, Dahiya. Cont.: 8146082832
- SM4 Jat Girl (DOB 03.09.90) 29.10/5'2" B.C. A., B.Ed. MSc. Employed as private school teacher in Chandigarh. Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Nandal, Lamba, Gahlayan. Cont.: 7696771747
- SM4 Jat Girl (DOB 23.11.91) 28/5'3" MSc. Physics from Kurukshetra University, B.Ed. Employed in State Bank of India as Trainee Officer/Probationary Officer on regular basis at Kaithal. Father retired from Mandi Board. Wanted educated match working in Govt. Sector, Banking or MNC Co. Avoid Gotras: Sangroha, Nain, Kaliraman. Cont.: 9466569366
- SM4 Jat Girl (DOB 29.09.90) 29/5'6" B.Tech (I.T), M.A. (English) from Punjab University Chandigarh. NET qualified. Preparing for PhD in English. Presently doing part time job at India-Canada Elante Offices at Chandigarh as Invigilator/Technician for CELPIP exam. Avoid Gotras: Nain, Chahal, Rathi, Shaharan. Cont.: 9463087328
- SM4 Jat Girl (DOB 13.10.91) 28/5'5" B.A. LLB (Hons.) LLM, Pursuing PhD from MDU Rohtak. Advocate in Punjab & Haryana High Court. No dowry seeker. Preferred match from Chandigarh, Panchkula, Mohali. Own flat at Panchkula. Avoid Gotras: Malik, Deswal. Cont.: 9417333298
- SM4 Jat Boy (DOB14.03.95) 25/5'10" B.A. Employed in M. C. Chandigarh as Clerk on contract basis. Family settled in Panchkula. Avoid Gotras: Sangwan, Jakhar, Panchar Cont.: 9463961502
- SM4 Jat Boy (DOB 08.10.91) 28/5'9" B.Tech. in Mechanical Engineering. Employed in a reputed company as Senior Engineer. Family settled in Pinjore. Avoid Gotras: Malik, Balyan. Cont.: 9466015020
- SM4 Jat Boy 30.6/5'7" B.Tech. Employed as Project officer in department of New & Renewable Energy Haryana in Head office Panchkula. Avoid Gotras: Mahalia, Kadwasra, Bhuria. Cont.: 9417250704
- SM4 Jat Boy (DOB 08.10.90) 29/5'11" Bachelor in Computer Application. Employed in Sarv Haryana Gramin Bank. Avoid Gotras: Dahiya, Chhikara, Sehrawat. Cont.: 9417091551, 6283122797
- SM4 Jat Boy (DOB 05.10.89) 30/5'8" 12th passed, Sanitary Inspector dip. Own business. Avoid Gotras: Dahiya, Raman. Cont.: 7206038345
- SM4 Jat Boy (DOB 20.04.91) 29/5'8" B.Tech. Computer Science. Self company at Gurgaon. Mother in Haryana Government. Avoid Gotras: Kadian, Ahlawat, Dagar. Cont.: 9876855880
- SM4 Jat Boy (DOB 17.10.89) 30/6 feet B. Tech. CSC. Employed as Inspector (GST & Central Excise) at GST & Excise Commissionrat at Surat (Gujrat) with Rs. 70000/- PM. Area preferred: Panchkula, Chandigarh, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Hisar. Avoid Gotras: Malik, Jattan, Punia. Cont.: 9996858234
- SM4 Jat Boy (DOB 10.08.92) 28/5'10" M.Sc. Geography. Job Car Workshop with Rs. 3-4 lakh PA. Mother employed in ICDC department. Agriculture land 18 acre. Avoid Gotras: Pannu. Cont.: 9466848433
- SM4 Jat Boy (DOB 03.10.90) 29/6 feet B.Tech. (Mechanical) from LPU Jalandhar. Employed as Senior Auditor in C & AG at Banglaru. Father retired S.M. now working as Admn. Officer in Mankind Pharma Co. Avoid Gotras: Dhankhar, Sangwan, Suhag. Cont.: 8219949508, 9805967450
- SM4 Jat Boy (DOB 30.06.92) 28/6 feet B.Tech. Employed in a reputed Company at Mohali with Rs. 4 lakh package PA. Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Sindhu, Tehlan, Dhanda. Cont.: 9872716234, 9417345494
- SM4 Jat Boy (DOB 05.03.88) 32/6 feet B.C.A., MBA, Oracle Course from Pune. Employed as Assistant Consultant in Capgemini Technology Services India Pvt. Ltd. with salary Rs. 50000/- per month. Father advocate. Preferred match in job. Avoid Gotras: Singhal, Sidhu. Cont.: 9013477708, 9810432497
- SM4 Jat Boy (DOB 22.08.87) 33/5'8" M.A. (Political Science) from MDU Rohtak. Pursuing PhD from MDU. Employed as Assistant Professor on contract basis in Bhagat Phool Singh University Khanpur with Rs. 7.50 lakh salary PA. Father ETO retired. Preferred MA, M.Sc, BA/B.Sc girl. Avoid Gotras: Dahiya, Siroha. Cont.: 9810493883
- SM4 Jat Boy (DOB16.04.95) 25/5'7" 10+2, Non-Medical, Graduation, M.A. 1st year, HARTRON Diploma. Avoid Gotras: Malik, Dalal, Ghanghas. Cont.: 9888991799
- SM4 Jat Boy (DOB 28.10.92) 27/5'9" B.Tech. (Mechanical) from Kurukshetra University. Employed as Senior Production Engineer in Stylam Industries Pvt. Ltd. at Raipur Rani (Panchkula). Father in govt. job at Panchkula. One flat at Dhakoli, 3 acre land, one residential house, two plots and 1 Service Station at Village Badauli (Panipat). Avoid Gotras: Mittan, Kharb, Dahiya. Cont.: 8146082832

सफला आवश्यक नहीं है, किंतु प्रकाश का अनुकरण करना मेरे लिए आवश्यक है। -अब्राहम लिंकन

सार्वजनिक अपील

जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समस्त विश्व कोरोना वायरस की महामारी के संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसने आमजन के स्वास्थ्य के साथ-साथ राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था को भी डांवाडोल कर दिया है। हरियाणा भी इस महामारी से अछूता नहीं हैं, दिन-प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह जानलेवा बीमारी लम्बे समय तक चल सकती है।

देश एवं प्रदेश में विकट हालातों के मध्यनजर जाट सभा द्वारा अपने दोनों भवनों :- सैक्टर-27, चण्डीगढ़ जाट भवन तथा सैक्टर-6, पंचकूला में स्थित सर छोटूराम भवन तथा चौधरी छोटूराम सेवा सदन कटरा-जम्मू के 10 कनाल के प्लॉट को कोरोना से संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए संबंधित प्रशासन/सरकारों को सौंप दिया गया है। पंचकूला स्थित सर छोटूराम भवन तो स्वास्थ्य विभाग पंचकूला के उन डाक्टरों की टीम को रहने के लिए दिया गया है जो कोरोना से संक्रमित मरीजों को ईलाज करने में सेवारत है।

जाट सभा पंचकूला/चण्डीगढ़ हमेशा ही समाजसेवा के कार्यों में अग्रणी रहती है। वर्तमान कोरोना की महामारी के संकट को देखते हुए जाट सभा ने पीड़ितों की सहायता के लिए **'हरियाणा कोरोना रिलिफ फंड'** में **1 लाख 11 हजार रुपये** की राशि अनुदान में दी है, यह प्रयास सभी के सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। जाट सभा पंचकूला/चण्डीगढ़ के पास इस प्रकार की आपदाओं या महामारी के लिए अपना कोई स्थाई कोष नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में आप सभी दानी सज्जनों के सहयोग से वित्तीय अनुदान का प्रबंध किया जाता है।

इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक आपदा की इस घड़ी में सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी इच्छा अनुसार भरपूर आर्थिक सहयोग एवं हर संभव सहायता प्रदान करें। इसके साथ ही इस भयंकर बीमारी से बचाव हेतू सरकार द्वारा घोषित कर्फ्यू/लॉकडाऊन व इस संदर्भ में जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

जाट सभा को दी जाने वाली अनुदान राशि 'जाट सभा चण्डीगढ़' के पक्ष में चैक/डिमांड ड्राफ्ट की मार्फत जाट भवन, 2 बी, सैक्टर-27ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़-160019 में भेजी जा सकती है। इसके अलावा, धनराशि एनएफटी/आरटीजीएस द्वारा जाट सभा चण्डीगढ़ के बचत खाता नम्बर-5010023714552, आईएफएससी कोड - एचडीएफसी 0001321 में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा-80 सी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : **डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)**
सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932, 2641127
Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला
फोन : 0172–2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172-2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।